epaper
हिन्दुस्तान

भाजपा के संकल्प पत्र पर विभागों ने शुरू किया मंथन, किसानों को मुफ्त बिजली पर 2200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा

किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी

3.06
करोड़ कुल विद्युत उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश में

13.16
लाख इनमें से नलकूप उपभोक्ता (किसान) हैं

बिजली पर सब्सिडी 13 हजार करोड़ से अधिक

सरकार पहले से ही बिजली पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये सालाना सब्सिडी दे रही है। इस योजना को लागू करने पर सब्सिडी बढ़कर 13 हजार करोड़ से अधिक हो जाएगी। पावर कारपोरेशन की मौजूदा स्थिति यह है कि यह कारपोरेशन करीब 95 हजार करोड़ रुपये के घाटे में है।

13/03/2022

लखनऊ प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में सत्ता की बागडोर फिर से संभालने की तैयारी में जुटी भाजपा अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने के साथ ही "भाजपा का संकल्प बनेगा यूपी नंबर वन" को पूरा करने में जुटेगी। घोषणा पत्र पर विभागों ने मंथन शुरू कर दिया है। इन्हें अमलीजामा पहनाने की कार्ययोजना क्या होगी व्ययभार क्या आएगा इसकी रूपरेखा खींची जा रही है। भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्जमाफी के फैसले की तरह इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने का प्रस्ताव ला सकती है।

सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग को सब्सिडी देगी: किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने में क्या व्ययभार आएगा इस पर ऊर्जा विभाग में मंथन शुरू हो गया है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने में 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ अनुमानित है। वादे को पूरा करने के लिए सरकार यह धनराशि सब्सिडी के रूप में पावर कारपोरेशन को देगी।

डाक्टरों व पैरामडिकल स्टाफ की भर्ती जल्द होगी : दूसरी तरफ बताया जाता है कि प्रदेश में समूह "ग" के ही 40 हजार पद रिक्त हैं। इनके संबंध में प्रस्ताव पहले से तैयार है। भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में 6000 डाक्टरों तथा 10 हजार पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति जल्द करने का वादा किया है।

स्कूटी देने को तय होगी मेधावी की परिभाषा

उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की भाजपा की घोषणा पर अमल करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए शासन के आला अधिकारी मेधावी की परिभाषा तय करने में जुट गए हैं। इसके अलावा उज्जवला योजना के तहत पात्रों को होली परमुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की तैयारी है।

भाजपा के लोक संकल्प पत्र में शामिल मुद्दों में छात्राओं से संबंधित यह बिन्दु काफी अहम है। भाजपा ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का वादा है। माना जा रहा है कि छात्राओं के आंकड़े जुटाने के बाद सरकार अपने बजट के हिसाब से मेधावी की परिभाषा तय करेगी। इसमें इंटरमीडिएट के अंकों को भी आधार बनाया जा सकता है। पीजी की छात्राओं को स्कूटी दिए जाने की स्थिति में स्नातक के अंकों को आधार बनाया जा सकता है।

3.06
करोड़ कुल विद्युत उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश में

13.16
लाख इनमें से नलकूप उपभोक्ता (किसान) हैं

तोहफा

विभागीय रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा

कुछ माह पूर्व सरकार ने विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव विभागों से मांगे थे। करीब करीब सभी विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे थे। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को नये सिरे से बनाने की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव से पूर्व मुख्य सचिव के स्तर पर भी रिक्तियों को भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हुई थीं। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेस) के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य व परिवहन जैसे विभाग करीब 30 फीसदी कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में स्वीकृत पद 7500 हैं जिसके सापेक्ष महज 2200 स्थाई कर्मचारी हैं। आउटसोर्स के सहारे अधिकांश काम चल रहे हैं। वादे के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम तेजी से करना होगा।

बिजली पर सब्सिडी 13 हजार करोड़ से अधिक

सरकार पहले से ही बिजली पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये सालाना सब्सिडी दे रही है। इस योजना को लागू करने पर सब्सिडी बढ़कर 13 हजार करोड़ से अधिक हो जाएगी। पावर कारपोरेशन की मौजूदा स्थिति यह है कि यह कारपोरेशन करीब 95 हजार करोड़ रुपये के घाटे में है।

1000 करोड़ की योजना नंदबाबा दुग्ध मिशन पर भी किया गया मंथन

सूत्र बताते हैं कि भाजपा के संकल्प में खेती किसानी और किसानों की खुशहाली के लिए शामिल करीब 37 हजार करोड़ की योजनाओं पर भी संबंधित विभागों ने काम शुरू किया है। शपथ के बाद जैसे-जैसे सरकार का निर्देश मिलेगा संबंधित घोषणाओं से संबंधित कार्ययोजना सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे।

राज्य में डेयरी वैल्यू चेन बनाने की योजनाओं पर काम पहले से ही चल रहा है। बुंदेलखंड की बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर समूह की तर्ज पर पूर्वांचल में दो दुग्ध उत्पादक कंपनियों के गठन की योजनाओं को स्वीकृत भी किया जा चुका है। भाजपा की घोषणा पत्र में शामिल 1000 करोड़ की लागत से नंदबाबा दुग्ध मिशन के तहत उत्पादन को और बढ़ाने की योजना पर भी विभागीय स्तर पर मंथन होने लगा है।